लघु उद्योगों में रुग्णता

3185. **डा. जिनेन्द्र कुमार जैन :**

श्री विरेन जे. शाह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विगत कुछ वर्षों से उद्योगों में अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के कारण देश में चल रहे लघु उद्योगों में रुग्णता आती जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक अंतिम अनुमान के अनुसार देश में 2.45 लाख ऐसी लघु इकाइयां हैं जो रुग्ण हो गयी हैं और जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए कुल औद्योगिक ऋण का लगभग 37.5 प्रतिशत भाग लगा हुआ है;

(ग) यदि नहीं तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा बढ़ती हुई रुग्णता की रोक-थाम के लिए गत छह माह के दौरान उद्योगों को विशेष रूप से लघु उद्योगों को दिए जाने के लिए घोषित सुविधाओं और रियायतों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च, 1992 तक रुग्ण लघु उद्योग एककों की संख्या 2.46 लाख थी और रुग्ण लघु उद्योग एककों के नाम बकाया बैंक ऋण की राशि उद्योग को दिये गये कुल बैंक ऋणों का 4.7 प्रतिशत थी ।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 17 अप्रैल, 1993 और 3 जुलाई, 1993 के परिपत्र द्वारा अन्य बातों के अलावा रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनर्वास के बारे में नायक समिति की सिफारिशों पर भी कार्यवाही की थी । ये निम्नलिखित से संबंधित हैं रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की संशोधित परिभाषा, रुग्ण एककों के पुनर्वास पर ली जाने वाली ब्याज की कम दर, किसी एक को रुग्ण मान लिया जाने के बाद जीव्यता अध्ययन/पुनर्जीवन कार्यक्रम क्रमशः 3 महीने और 6 महीने के भीतर आरंभ करना । इसके अलावा, लघु औद्योगिक एककों में रुग्णता की समस्या से शीघ्रता से निपटने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की सलाह दी है कि वे रुग्ण औद्योगिक एककों की देखरेख करने के लिए मुख्यालय स्थित प्रकोष्ठ के अलावा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कार्यालयों में भी प्रकोष्ठ गठित करें तथा तकनीकी पहलुओं को देखने के लिए तकनीकी कार्मिकों सहित विशेषज्ञ स्टाफ की व्यवस्था करें ।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में पूंजी निवेश

3186. **डा. जिनेन्द्र कुमार जैन :**

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में संचालित सरकारी क्षेत्र के 246 उद्यमों में कुल 1,35,875 करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है ;

(ख) यदि नहीं, तो मार्च 1993 में यह आंकड़ा कितना था;

(ग) कुल निवेश में से विदेशों से ऋण के रूप में प्राप्त विदेशी पूंजी का अंश कितना है और उस पर प्रतिवर्ष कितना ब्याज दिया जा रहा है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन उद्योगों ने वर्षवार कितना-कितना लाभ कमाया ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साहो) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1992 तक की जानकारी उपलब्ध है और उसके अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 246 उद्यमों में 1,35,871 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश किया गया था ।

(ग) 31-3-1992 तक विदेशों से प्राप्त ऋण के रूप में विदेशी पूंजी 28112.98 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1991-92 के दौरान ऐसे ऋणों पर चुकाए गए ब्याज की राशि 1805.33 करोड़ रुपये थी।

(घ) विगत तीन वर्ष के दौरान सरकारी उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ का उद्यम-वार ब्यौरा 26 फरवरी, 1993 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1991-92 के खण्ड-1 के विवरण-संख्या 7 "क" में दिया गया है।

देश में चल रहे भारी उद्योग

3187. **श्री राम जेठमलानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत मार्च 1993 की स्थिति के अनुसार कुल कितने भारी उद्योग चल रहे थे तथा उनमें विदेशी ऋणों के रूप में प्राप्त राशि सहित कुल कितनी पूंजी लगी थी;

(ख) इन उद्योगों में विदेशी ऋण के रूप में कुल कितनी पूंजी लगी थी और उस पर वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान कितना ब्याज देना पड़ा;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन उद्योगों को वर्ष 1992-93 में भारी घाटा हुआ है;

(घ) यदि हां तो उक्त वित्तीय वर्ष में इनको कुल कितना घाटा हुआ और किन-किन उद्योगों को पिछले तीन वर्षों से लगातार घाटा हो रहा है;

(ङ) क्या सरकार ने कतिपय उद्योगों के मामलों को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास विचारार्थ भेजा है; यदि हां तो उनकी संख्या कितनी है; और

(च) सरकार ने उनके प्रति क्या नीति अपनाने का निर्णय लिया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) उद्योग मंत्रालय के अधीन 31 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के 48 उपक्रम चल रहे हैं। इन उपक्रमों में नियोजित पूंजी विदेशी ऋण तथा उन पर वर्ष 1992-93 के दौरान देय ब्याज की राशि के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और इस बारे में एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है। (नीचे देखिये) 26 उपक्रम पिछले 3 वर्षों से लगातार घाटे में चल रहे हैं।

(ङ) जी हां। 19 उपक्रमों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को संदर्भित किया गया है।

(च) प्रत्येक मामले में सरकार की नीति सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद ही निर्धारित की जाएगी।

विवरण

भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में गत तीन वर्षों के दौरान लाभ (+) हानि (—) दर्शाने वाला विवरण।

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के नाम	1990-91	1991-92	1992-93
1.	एन्ड्रयूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड	11.00	8.15	3.77
2.	भेल	201.46	186.65	309.00
3.	बर्न स्टण्डर्ड कंपनी लिमिटेड	—3.44	—9.02	—3.20
4.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लिमिटेड	—1.95	—1.77	—0.61
5.	रेरोल बर्न लिमिटेड	—1.19	—1.07	—0.94
6.	जेसप एन्ड कम्पनी लिमिटेड	—1.38	—4.61	—9.72